

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 618वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्षय महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No. 9290/2022 M/s Piyanshu Chemicals Pvt. Ltd, 53A, Tiljala Road, Mescab Centre, 4th Floor, Kolkata, W.B. – 700046. Prior Environment Clearance for Expansion in production capacity from 8320 MT/Year to 48,000 MT/Year for Manufacturing of Resins, Driers, Paint Additives Products at Plot No. 684, 652, Industrial Area-3, Pithampur, Dist. Dhar, MP. Cat. - 5(f) Env. Cons. – M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).**

The project is a Synthetic Organic Chemicals Industry (dyes & dye intermediates; bulk drug). Cat.- 5(f) Synthetic Organic Chemicals Industry (As per EIA notification dated 14th September 2006 and amended to the date) and involves environmental clearance. Application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 594<sup>th</sup> SEAC dated 21/09/2022 wherein ToR was recommended. TOR approved in 751 SEIAA meeting dated 14-10-22. TOR issued letter no. 1856- 57/SEIAA/22 dated 20/10/2022. PP has submitted the EIA report Online which was forwarded by and the same was scheduled in the agenda.

The case was presented by Env. Consultant Env. Consultant Shri Manish Chandekar (Online) and Ms Vasanti Tapadia from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and on behalf of PP Shri Padmanabh Bhagat., wherein during presentation PP submitted that M/S Piyanshu Chemicals Private Limited (PCPL) has its manufacturing unit at Plot No 684 & 652, Industrial Area-3, Pithampur, Dist. Dhar, M.P. Company is manufacturing Resins,

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

Driers, Paint Additives products with the total production capacity of 8320 MTPA under Valid Water and Air Consents from MP Pollution Control Board wide its letter no .2150/RO-Dhar/MPPCB/05dtd 12.09.2005. Now PCPL is proposing the expansion in the production capacity of above products and has applied for Consent to Establish – Expansion wide its Application No.-1166220 and has obtained CTE expansion via MP Pollution Control Board Letter no CTE-56224 dated 30.06.2022. One of the conditions prescribed under consent is to obtain Prior Environmental Clearance for the proposed Expansion. Therefore, to obtain Prior EC, the application is being made for EC under 5(f)-Other Synthetic Organic Chemicals. The total land area acquired for the project is 12281 Sq. meter. The capital cost of the project is 24 Crores INR.( 12.36 is Existing & 11.64 is Proposed cost). This is to your kind notice that we have uploaded consent for air & water with consent no. 2150/RO-Dhar/MPPCB/05 Dated. 12.02.2005 validity upto 31.05.2008. We have renewed the same consent again & previous consent no. AW-54627 dated 16.11.2021, validity 14.09.2022. We have again applied for renewal of consent for 1 year which is awaited & expected consent validity is 14.09.2023.

PP further submitted that the product profile has been finalized based on the market demand and the technology compatibility. The process involves essentially reacting the raw materials drawn from various sources. The product profile is finalized taking into consideration the reaction yields, waste profile, hazardous nature of raw materials. The existing and proposed products for EC are in given below table.

Existing Products		
S. No.	Product list	Quantity in MTPA
1	Amino Resin	360
2	Synthetic Resin	6400
3	Driers	360
4	Paint & Varnish	600
5	Thinner	600
<b>Total</b>		<b>8320</b>
Proposed Products for EC		
S. No.	Product list	Quantity in MTPA
1	Amino Resin	3600
2	Synthetic Resin	28800
3	Driers	3600
4	Paint Additives	12000
<b>Total</b>		<b>48000</b>

During presentation, PP submitted that being our plant is situated in the Notified Industrial

**618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जनवरी 2023**

Area, public Hearing is not applicable and as the plant was established prior to the EIA Notification, 2006, applicability of EC was envisaged. During presentation, PP submitted that they have purchased additional land adjacent to this plant for green belt development. After presentation, PP was asked to submit clarification/details on following:

1. Revisd mass balance according corrections as suggested by the committee with justification for catalyst being taking part in the reaction.
2. Justify (with backup calculation) 59 KLD water loss through cooling tower as shown in water balance.
3. Revised water balance with its bifurcation for existing products and for expansion.
4. Backup calculation for carbon footprint calculations in quantifiable terms.
5. Clear lay out depicting exsiting facilities and proposed facilities for expansion.
6. Revised CER proposals as suggested by committee.
7. Revised plantation scheme as suggested by committee.

**2. Case No 8720/2021Shri Neeraj Agrawal, Near Kidzee School, Indrapuri Colony, Tehsil & Dist. Tikamgarh, MP - 472001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.90 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 236/1 Part), Village - Srinagar Bhata, Tehsil - Tikamgarh, Dist. Tikamgarh (MP) M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida, UP.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 236/1 Part), Village - Srinagar Bhata, Tehsil - Tikamgarh, Dist. Tikamgarh (MP) 1.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 522वीं दिनांक 27/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है, जिसके दक्षिण दिशा में 460 मीटर पर पक्का रोड़ एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में 700 मीटर पर जल संग्रहण क्षेत्र है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी खदान का पिट है जिसमें पानी भरा हुआ है तथा उनके द्वारा गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव दिया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पास से कच्चा रोड़

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हमारी खदान का पहुंच मार्ग है। आवंटित खनन क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल 04 पेड़ लगे हैं जो बैरियर जोन में होने के कारण काटा जाना प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन क्षेत्र में पुराना गढ़वा है तथा खदान हमें इसी स्थिति में 2021 में स्वीकृत हुई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-34 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा पानी की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऐरिया मैप के अनुसार वन क्षेत्र पूर्व दिशा में लगभग 25 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ वन मंडलाधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 2971 दिनांक 23/07/21 द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि आवेदित क्षेत्र से 250 मीटर की दूरी तक कोई वन क्षेत्र नहीं है। उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशंसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग लगभग 25 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मंडलाधिकारी से इस स्थिति को स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व से ही इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए वन मंडलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमंडल, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 6986 दिनांक 13/12/22 द्वारा पुनः जानकारी प्राप्त की गई है जिन्होंने सूचित किया है कि आवेदित क्षेत्र राजस्व का है तथा नजदीकी वन सीमा कक्ष क्रमांक 63ए से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि उनके द्वारा यह प्रमाण पत्र ई.आई.ए. के साथ ऑन लाईन अपलोड किया गया है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निम्नानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन — 15,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में क्वीटल राशि रु. 07.70 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.61 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जनवरी 2023**

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम श्रीनगर भाटा के लिए वर्ष में दो बार स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था	20,000 / –
गावँ श्रीनगर भाटा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 30W सोलर लाइट की स्थापना कराई जायेगी।	20,000 / –
ग्राम श्रीनगर भाटा में एक हैंड पंप की स्थापना की जायेगी।	30,000 / –
योग	70,000 / –

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2290 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, नीम, पीपल, खमेर, चिरौल, करंज, आदि उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1100
2	ग्राम श्रीनगर भाटा के शासकीय विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, सीताअशोक, नीम, कचनार, पुत्रंजीव, गुलमोहर इत्यादि।	30
3	ग्राम श्रीनगर भाटा और दुर्गापुर में वृक्षारोपण वितरण हेतु।	मुनगा, नींबू, अमरुद, मौसम्मी, इमली, सीताफल, आवला, बेल, आदि उपलब्ध देशी और औषधीयुक्त प्रजातियाँ	1050
4	अप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	नीम, पीपल, सिस्सू, बरगद, कदम, अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	110
<b>कुल</b>			<b>2290</b>

3. **Case No 8394/2021 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Lease Owner, Near Alka Talkies, Nehru Ward, Pipariya, Dist. Narmadapuram, MP - 461775, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (64800 cum per annum) (Khasra No. 276), Village - Panagar-2, Tehsil - Gadarwara, Dist. Narsinghpur (MP) (Old) M/s Dhanlaxmi Marchendais Pvt. Ltd, Shri Samar Singh Tomar, 501/pi/1, Ward No. 16, Civil Line, Kalika Nagar, Babai Road, Dist. Hoshangabad,**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 276), Village - Panagar-2, Tehsil - Gadarwara, Dist. Narsinghpur (MP) 6.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 911 दिनांक 10/10/2022 के द्वारा पारित आदेशानुसार यह खदान रसमीत सिंह मल्होत्रा, नर्मदापुरम को 30 जून, 2023 तक आवंटित/हस्तांतरित की गई है तथा सिया की 750वीं बैठक दिनांक 13/10/22 में हुए निर्णय अनुसार टॉर भी रसमीत सिंह मल्होत्रा, नर्मदापुरम के नाम से पत्र क्रमांक 2305 दिनांक 14/12/22 के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रसमीत मल्होत्रा (ऑनलाईन), उनके प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार डॉ जतिन श्रीवास्तव, मेसर्स पी एंड एम सल्यूशन, नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान दूधी नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान नदी के पूर्वी भाग में स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-02 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,51,000 मी.टन (1,08,000 घनमीटर) उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 64,800 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा धार्मिक कार्यों में सहयोग, स्कूल में पंखे लगवाये जाये एवं वृक्षारोपण किया जाये एवं रोजगार इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 64,800 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.53 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.02.01 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 09.57 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियाँ चयनित कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 7200 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर, नदी तट से 3 से 4 मीटर की दूरी पर	कटगबांस, नागरमोथा, खस, ढेंचा, करंज, जामुन, कहवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ (1 मीटर ऊँचाई के पौधे)	2500
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (कैचमेंट क्षेत्र, रिपेरियन क्षेत्र,)	आमाहल्दी, लक्ष्मणकन्ध, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केवकंध, कालमेघ, एवं अन्य प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	1000
3	परिवहन मार्ग	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, जंगलजलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ (1 मीटर ऊँचाई के पौधे)	1000
4	ग्राम पंचायत पनागर के प्राथमिकशाला, आंगनवाड़ी, पूजा स्थलों, ग्राम पंचायत परिसर एवं जनपद पंचायत की भूमि पर	नीम, आम, धावड़ा, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, बहेड़ा, बेल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	450
5	आवंटित क्षेत्र के आसपास के ग्राम में तथा पनागर ग्राम के ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत पनागर)	नीम, आम, धावड़ा, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, बहेड़ा, बेल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2250
Total			7200

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.68 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Installation of Fan (twelve units @ Rs 1500/unit, hand pump (one @ Rs 100,000/) in the school building (as per public hearing)	1,18,000/-
Construction of Pukka chabutra (size 5'× 8') in nearby worship place of village Panagar (as per the discussion of public hearing)	50,000/-
2-Speed Breaker both side before the Shala Bhavan Panagar as asked by the natives of village Panagar during public hearing	50,000/-
Providing 1 wheel chair and 2 medical beds in PHC Panagar	50,000/-
Total	2,68,00/-

**4. Case No 8393/2021 Shri Rasmeet Singh Malhotra, Lease Owner, Near Alka Talkies, Nehru Ward, Pipariya, Dist. Narmadapuram, MP - 461775, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 10.0 ha. (1,35,000 cum per annum) (Khasra No. 207), Village - Sansarkheda-2, Tehsil - Gadarwara, Dist. Narsinghpur (MP) (Old Name) M/s Dhanlaxmi Marchendais Pvt. Ltd, Shri Samar Singh Tomar, 501/pi/1, Ward No. 16, Civil Line, Kalika Nagar, Babai Road, Dist. Hoshangabad,**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 207), Village - Sansarkheda-2, Tehsil - Gadarwara, Dist. Narsinghpur (MP) 10.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया की 750वीं बैठक दिनांक 13/10/22 में हुए निर्णय अनुसार टॉर श्री रसमीत सिंह मल्होत्रा, नर्मदापुरम के नाम से पत्र क्रमांक 2305 दिनांक 14/12/22 के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रसमीत मल्होत्रा (ऑनलाईन), उनके प्रतिनिधि श्री अभिषेक निगम और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार डॉ जतिन श्रीवास्तव, मेसर्स पी एंड एम सल्यूशन, नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान दूधी नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान नदी के मध्य भाग में स्थित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-02 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-2,52,000 मी.टन (1,80,000 घनमीटर) उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 1,13,400 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा धर्मिक कार्यों में सहयोग, स्कूल में वृक्षारोपण एवं पानी की व्यवस्था एवं रोजगार इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई. आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण को दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर 1,35,000 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु लिया गया था किंतु फार्म-1 एवं ई.आई.ए. रिपोर्ट 1,13,400 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु प्रस्तुत की गई है अतः पर्यावरण अभिस्वीकृति भी 1,13,400 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष हेतु दी जाना अनुशंसित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 1,13,400 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.53 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.37 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 13.50 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर स्वयंम वृक्षो की प्रजातियाँ चयानित कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे ।

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 3500 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर, (Riparian Zone) नदी तट से 3 से 4 मीटर की दूरी पर	कटगबांस, नागरमोथा, खस, डेंचा, करंज, जामुन, कहवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ (1 मीटर ऊँचाई के पौधे)	3000
2	आवंटित लीज़ क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (कैचमेंटक्षेत्र)	आमाहल्दी, लक्ष्मणकन्ध, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केवकंध, कालमेघ एवं अन्य प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	1000
3	परिवहन मार्ग	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ (1 मीटर ऊँचाई के पौधे)	1000
4	ग्रामपंचायत संसारखेडा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी, पूजा स्थलों, ग्राम पंचायत परिसर एवं जनपद पंचायत की भूमि पर	नीम, आम, धावड़ा, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, बहेड़ा, बेल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3500
5	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, धावड़ा, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, बहेड़ा, बेल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3500
Total			12000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Installation of hand pump (one @ Rs 100,000/-) in the school (Prathmik Shala Sansar Kheda village (as per public hearing discussion)	100,000/-
Repairing of fence, painting of walls and construction of Chabutra (5'x 8') at temple in Sansar Kehda village (as per public hearing discussion)	50,000/-
Training of (wood carving) carpentry & sewing to the local natives of working age group for development of entrepreneurship along with distribution of two sewing machines and tools for wood carving.	80,000/-
Providing two wheel chairs and one Medical Bed shall be donated to the PHC Sansar Kheda Village.	50,000/-
<b>TOTAL</b>	<b>2,80,000/-</b>

**618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जनवरी 2023**

5. **Case No 7828/2020 M/s Bhagchand Sancheti, Partner, Shri Gaurav Sancheti, Nehru Chowk, Waraseoni, Dist. Balaghat, MP - 481331 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 5.80 ha. (50000 tonne per annum) (Khasra No. 239, 240, 278/2), Village - Ambejhari, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP)**

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 239, 240, 278/2), Village - Ambejhari, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) 5.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 618वीं बैठक दिनांक 11/01/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

6. **Case No 9549/2022 PANKAJ GUPTA, Owner, 101 Shrinagar main Road, Khajrana Road, Indore, District Indore Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.730 ha. (17,500 m3/year) Khasra No. 82, Village BHILAKHERA Tehsil & district - Dewas (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No. 82, Village BHILAKHERA Tehsil & district - Dewas (MP) 3.730 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2888 दिनांक 21/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है। इस खदान का कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 750 मीटर पर मंदिर, दक्षिण दिशा में 35 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 320 मीटर पर पक्का रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। इसी प्रकार खदान के बीच में पिट है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह बहुत पुराना पिट है

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

तथा हमको खदान इसी स्थिति में 03/08/22 में आवंटित हुई है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पास में एक पहाड़ स्थित है जिसका बारिश के दौरान रन-ऑफ खदान में आने की संभवना होगी अतः रन-ऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2986 दिनांक 16/11/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट सिया से अनुमोदित की जा चुकी है। उक्त उत्खनिपट्टा का संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी । अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पूर्व दिशा में 750 मीटर पर मंदिर, दक्षिण दिशा में 35 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 320 मीटर पर पक्का रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. इसी प्रकार खदान के बीच में पिट है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह बहुत पुराना पिट है तथा हमको खदान इसी स्थिति में 03/08/22 में आवंटित हुई है अतः इस संबंध में प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ स्थिति ई.आई.ए. में स्पष्ट की जावे ।?
3. आवंटित खनन क्षेत्र के पास में एक पहाड़ स्थित है जिसका बारिश के दौरान रन-ऑफ खदान में आने की संभवना होगी अतः रन-ऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉपट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. चूंकि आवंटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

**618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जनवरी 2023**

**7. Case No 9539/2022 M/s Sisodiya Enterprises , Owner Shri Govind Singh, Silegarh, Panchpahad, Dist Mandsaur (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.50 ha. (35312 m<sup>3</sup>/year) (Khasra No. 487), Village- Junapanipaavti, Tehsil-Garoth, District-Mandsaur (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 487), Village- Junapanipaavti, Tehsil-Garoth, District-Mandsaur (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोविंद सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 996 दिनांक 12/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.500 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पूर्वी भाग में 200 मीटर की दूरी पक्की सड़क तथा पश्चिम भाग में 170 मीटर पर मौसमी नाला है तथा आवंटित खनन क्षेत्र से भी मौसमी नाला उदगमित हो रहा है जिनके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मौसमी नालों को गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेक के माध्यम से चेनेलाईज किया जाना प्रस्तावित किया गया है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 1627 दिनांक 12/07/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 35,312 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12.85 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.83 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम जूनापानी पावटी शासकीय स्कूल में लोहे का गेट एवं टॉयलेट निर्माण	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	1500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, चिरोल एवं अन्य प्रजातियाँ	400
3	गाँव में वितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू, मुनगा एवं अन्य प्रजातियाँ	1200
4	स्कूल में	आम, मुनगा, नीम	400
कुल			3500

**8. Case No 9449/2022 Shri Prince Bansal, Lease Owner R/o Main Road Chachariya, Tehsil Sendhwa, District Barwani (MP)-451666 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (7866 Cum per year) (Khasra No. 385), Village - Dhanora, Tehsil - Sendhwa, Dist. Barwani (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 385), Village - Dhanora, Tehsil - Sendhwa, Dist. Barwani (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 611वीं बैठक दिनांक 14/12/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 618वीं दिनांक 11/01/23 एवं 611वीं दिनांक 14/12/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में

**618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जनवरी 2023**

रुचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

- 9. Case No 9477/2020 M/s SHIV LALJI CONSTRUCTION LLP, Shri Shandeep Madhwani, Director, 7<sup>th</sup>, Gulmarg Complex, Sapna Sangeeta, Main Road Indore(MP)-452001. Prior Environment Clearance for Construct Commercial Project at Plot No. D-69, Scheme No-151 & 169 B (Super Corridor) Indore M.P., Total Plot Area: 10560.85 m<sup>2</sup>, Total Built up Area - 29517.88 m<sup>2</sup>, Cat. 8(a), Env. Con.- M/s. Envisolve LLP Indore (M.P).**

This is a case of Prior Environment Clearance for Construct Commercial Project at Plot No. D-69, Scheme No-151 & 169 B (Super Corridor) Indore MP. Total Plot Area: 10560.85 m<sup>2</sup>, Total Built up Area - 29517.88 m<sup>2</sup>, at Village - Sindoda & Rangwasa, Tehsil - Rau, Dist. Indore, (MP).

The case was scheduled for the presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment desired by the committee during the deliberation. Committee decided to call the PP in subsequent meetings giving last chance and even if the PP remains absent, the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

The case was presented by PP Shri Shandeep Madhwani, Director and there Consultant Shri Pradeep Chandana & Shri. Shubham Dubey (online) from M/s. Envisolve LLP, Indore (M.P.). During presentation, PP submitted that due to typographical error they have made some mistakes in the calculations of FAR, Builtup area, Parking & water details in uploaded application and requested to make necessary corrections/amendments which was considered by the committee and asked PP to submit revised details within 15 days for further considerations of the project.

- 10. Case No 9533/2022 Samant Sikarawar, Gram & Post Arhela Tehsil Joura District Morena (M.P.) Prior Environment Clearance for Arhela Soil Quarry in an area of 1.0 ha. (2500 cum per annum) Khasra No. 1320, Village.-Arhela, Tehsil-Joura, District-Morena (M.P.)**

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No. 1320, Village.-Arhela, Tehsil-Joura, District-Morena(M.P.) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

आज दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री समानत सिकरवार और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 182 दिनांक 11/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पूर्व दिशा में 110 मीटर पर नहर, पश्चिम दिशा में 185 मीटर पर कच्चा रोड़, पश्चिम दिशा में 300 मीटर पर आबादी तथा उत्तर दिशा में 70 मीटर पर पक्का रोड़ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन के दौरान ड्रिलिंग ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, खनन कार्य अधिकतम 02 मीटर की गहराई तक किया जायेगा, आवंटित खनन क्षेत्र में क्लिन की स्थापना नहीं की जायेगी तथा उत्तर दिशा में पक्के रोड़ के कारण 30 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-40 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्वाईल – 2500 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.16 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.11 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.54 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
अरहेला अंगनवाड़ी में पुताई एवं मरम्मत का कार्य किया जाएगा एवं बच्चों को खेलों दिये जाएंगे।	54,000 / -

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200

**618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जनवरी 2023**

3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, गुल, आवलौ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
			कुल 1200

**11. Case No 9498/2022 Shri Amit Raghuwanshi, Owner, R/o Village-Nateran, Tehsil-Nateran, District-Vidisha (MP)-464258 Prior Environment Clearance for Nagtara Murrum Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 297), Village – Nagtara, Tehsil - Nateran, Dist. Vidisha (MP)**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 297), Village – Nagtara, Tehsil - Nateran, Dist. Vidisha (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमित रघुवंशी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1649 दिनांक 07/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के दक्षिण दिशा में 45 मीटर पर कच्चा रास्ता, उत्तर दिशा में 360 मीटर पर अद्योसंरचना का निर्माण तथा पूर्व दिशा में 600 मीटर पर नहर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में खनन की गतिविधियां संचालित होना दिख रही है जबकि एक प्रमाण पत्र में 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत न होना दर्शाया गया है। अतः इस संदर्भ में समिति ने निर्णय लिया कि संबंधित खनिज अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये।

**12. Case No 9193/2022 Shri Jitendra Yadav, Owner, A-2, Mandakini Block, Kevihgar Line 1, Batalian, Dist. Indore, MP - 453111 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.20 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 178/228/1), Village – Alwasa Tehsil Mhow, Dist. Indore (MP)**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 178/228/1), Village - Alwasa, Tehsil - Hatod,

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

Dist. Indore (MP) 1.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 122 दिनांक 10/01/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई (01 उत्खनन पट्टा स्वीकृत जो मा. न्यायालय के आदेश से शिथिल अवस्था में) खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर के अंदर एक उत्खननपट्टा स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय के आदेश पालन में शिथिल अवस्था में है। समिति को उपरोक्त एकल प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव इस खदान पर भी लागू है या नहीं। अतः इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक से मा. उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के बारे में जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी उनके पास इस संदर्भ में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः जानकारी प्रदाय करने हेतु 10 दिन का समय दिया जाये। अतः समिति की अनुशंसा है कि मा. उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण की अद्यतन वस्तुस्थिति से 10 दिनों में अगवत कराया जाये, तत्पश्चात् प्रकरण विचार किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक ने ऑन लाईन जबाब 05/6/22 को प्रस्तुत किया, जिसे सेक की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण पुनः सेक की 586वीं बैठक दिनांक 29/06/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 05/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. नं. 18163/2019 में आदेश दिनांक 17/01/2020 के द्वारा बी.एस.एफ. की रेवती रेंज के समीप स्थित खदानों में निम्नानुसार खनन हेतु रोक लगाई गई :—

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

“The area which is subject matter of the present writ petition as well as the other areas which are under the Green Belt/hillocks no mining activity shall be carried out by any person including the State Government”.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आदेश के साथ उन 20 खदानों की सूची भी ऑन लाईन प्रस्तुत की है जो उपरोक्त आदेश के तहत बंद की गई है जिसमें से 04 खदानें उसी ग्राम अलवासा की हैं तथा जहां प्रश्नाधीन खदान भी है तथा कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) द्वारा पत्र क्रमांक 122 दिनांक 10/01/22 के माध्यम से जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर के अंदर एक उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय के आदेश पालन में शिथिल अवस्था में है ।

अतः उपरोक्त संदर्भ में समिति की अनुशंसा हेतु कि खनिज अधिकारी से 15 दिवस में यह जानकारी प्राप्त की जाये कि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. नं. 18163/2019 में आदेश दिनांक 17/01/2020 जारी दिशा निर्देशों के बावजूद भी प्रश्नाधीन खदान को क्यों स्वीकृती प्रदान की गई तथा क्या माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा जारी आदेश दिनांक 17/01/2020 इस खदान पर लागू नहीं होता । इस संदर्भ में खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् इस प्रकरण पर निर्णय लिया जावे ।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी 30 दिवस में अपलोड नहीं करने के कारण प्रकरण को सेकी 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 को डिलिस्ट करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित किया गया था । सिया के पत्र क्रमांक 1422 दिनांक 24/08/22 के द्वारा प्रकरण को डिलिस्ट किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/11/22 के द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट करने के अनुरोध को स्वीकार कर प्रकरण सिया द्वारा सेक को परीक्षण हेतु भेजा गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण रि-लिस्ट करने का ऑन लाईन अनुरोध दिनांक 24/12/22 को किया गया जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 11/01/2023 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र यादव और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए ।

प्रकरण के परीक्षण में समिति ने पाया कि पूर्व में यह प्रकरण सेक की 586वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में प्रस्तुत हुआ था जिसमें पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. नं. 18163/2019 में आदेश दिनांक 17/01/2020 के द्वारा बी.एस.एफ. की रेवती रेंज के समीप स्थित खदानों में निम्नानुसार खनन हेतु रोक लगाई गई :-

“The area which is subject matter of the present writ petition as well as the other areas which are under the Green Belt/hillocks no mining activity shall be carried out by any person including the State Government”.

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने निर्णय लिया था कि खनिज अधिकारी से 15 दिवस में यह जानकारी प्राप्त की जाये कि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. नं.

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

18163/2019 में आदेश दिनांक 17/01/2020 जारी दिशा निर्देशों के बावजूद भी प्रश्नाधीन खदान को क्यो स्वीकृती प्रदान की गई तथा क्या माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा जारी आदेश दिनांक 17/01/2020 इस खदान पर लागू नहीं होता । परियोजना प्रस्ताक ने पत्र दिनांक 09/11/22 (ऑन लाईन प्राप्ति दिनांक 24/12/22 ) के द्वारा खनिज अधिकारी जिला इंदौर का पत्र क्रमांक 1402 दिनांक 19/07/22 की फोटो प्रति संलग्न की है जिसमें खनिज अधिकारी ने सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 18163/2019 के आदेश की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम रेवती की भूमि, ग्रीनवेल्ट एवं पहाड़ी पर उत्खनन कार्य मान्य नहीं किया गया है । समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) द्वारा पत्र क्रमांक 122 दिनांक 10/01/22 के माध्यम से जारी एकल प्रमाण पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें उल्लेखित है कि इस खदान के 500 मीटर के अंदर एक अन्य उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जो कि वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय के आदेश पालन में शिथिल अवस्था में है ।

समिति ने चर्चा उपरांत पाया कि सेक की 586वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में की गई अनुशंसा अनुसार **माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. नं. 18163/2019 में आदेश दिनांक 17/01/2020 जारी दिशा निर्देशों के बावजूद भी प्रश्नाधीन खदान को क्यो स्वीकृती प्रदान की गई तथा क्या माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा जारी आदेश दिनांक 17/01/2020 इस खदान पर लागू नहीं होता, पर खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन 15 दिवस मागा जाये** के संदर्भ में संबंधित खनिज अधिकारी जिला इंदौर (पत्र क्रमांक 1402 दिनांक 10/07/22 के माध्यम से) द्वारा जो जानकारी दी गई थी वह सुस्पष्ट व समाधानकारक नहीं है तथा दिया गया उत्तर दिग्भ्रमित करने वाला है । अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार निर्मित स्थिति से कार्यालय कलेक्टर, इंदौर को सिया के माध्यम से अवगत कराया जाये ताकि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सुस्पष्ट जानकारी प्रकरण के अविलंब निराकरण हेतु प्राप्त हो सके ।

### **13. Case No 9378/2022 M/s Perfect Tar Coat Pvt. Ltd, Shri Sohail Ali Khan S/o Shri Mansoor Ali Khan, Director, 778, Napiar Town, Dist. Jabalpur, MP - 482001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (53,000 Cum per annum) (Khasra No. 98/1), Village - Dobhi, Tehsil - Narayanganj, Dist. Mandla (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 98/1), Village - Dobhi, Tehsil - Narayanganj, Dist. Mandla (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 604वीं बैठक दिनांक 05/11/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सोहेल अली खान (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 13/09/2022

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऐरिया मैप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग 220 से 230 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 13/09/2022) अनुसार वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 1249 दिनांक 17/06/22 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में कोई वन क्षेत्र नहीं है। उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशांसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 220 से 230 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इस स्थिति स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये। समिति की यह भी अनुशांसा है कि सिया द्वारा जो एकल-प्रमाणपत्र का प्रारूप दिया गया है उसमें डी.एफ.ओ. से यह स्पष्ट उल्लेख करवाया जाये कि प्रस्तावित खदान वन क्षेत्र से कितनी दूरी पर स्थित है एवं यदि खदान अधिसूचित ई.एस.जेड. के पास स्थित है तो वह ई. एस.जेड. से कितनी दूरी पर है तथा अधिसूचित ई.एस.जेड की सीमा से बाहर है ताकि प्रकरणों के निराकरण में सुविधा हो।

प्रकरण सेक की पूर्व की 614वीं बैठक दिनांक 23/12/22 को चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 दिनों तक जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण डिलिस्ट किये जाने हेतु एजेण्डा में सूचीबद्ध किया गया है, जिस सदर्थ में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए। पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परिवेश-2 पोर्टल लॉच किया गया है, जिसमें कुछ कठिनाईयाँ आने के कारण अभी ऑनलाईन जानकारी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, अतः उन्हें कुछ समय और दिया जाये, क्योंकि उनके द्वारा इस संबंध में परिवेश पोर्टल के संबंधित अधिकारी से दुरभाष/ई-मेल से सम्पर्क करने पर उक्त संबंध में शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है तथा वांछित जानकारी ई-मेल के माध्यम से सेक कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है। अतः उनके प्रकरण को डिलिस्ट न करते हुये 15 दिवस का समय और दिया जावे। समिति ने परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये 15 दिवस का समय दिया जाने का निर्णय लिया।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 11/01/2023 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Sohail Ali Khan (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वनमंडलाधिकारी, मंडला ने पत्र क्रमांक 2357 दिनांक 13/12/22 के माध्यम से सेक के पत्र क्रमांक 303 दिनांक 14/11/22 के सदर्थ में सूचित किया है कि प्रस्तावित खदान के 250 मीटर की परिधि में कोई वन क्षेत्र नहीं है। आवेदित खदान से वन भूमि की न्यूनतम दूरी 255 मीटर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुशांसा अनुसार आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर पक्का रास्ता एवं 310 मीटर पर आबादी तथा उत्तर-पश्चिम

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

दिशा में 125 मीटर पर शेड है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यहां पूर्व में केशर/कोलटार प्लॉट स्थापित था उसके शेड बने हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 53,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.35 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
डोभी प्राथमिक शाला में टॉयलेट निर्माण 02 ( पानी की उचित व्यवस्था के साथ)	1,50,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	2000
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	चिरोल, करंज, जंगल जलेबी एवं अन्य प्रजातियाँ	200
3	गाँव में वितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू, मुनगा एवं अन्य प्रजातियाँ।	1000
4	निजी भूमि खसरा न .96	नीम, आम, करंज, सीताफल, मुनगा एवं अन्य प्रजातियाँ	1800
कुल			5,000

### **14. Case No 9456/2022 Shri Abhishek Kumawat, Leasee, R/o Villag Chakrawada, Tehsil Ghattiya, District Ujjain (MP)-456001 Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 16/1, 97/1/1, 97/1/2), Village - Madhawgarh, Tehsil - Ghattiya, Dist. Ujjain (MP)**

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 16/1, 97/1/1, 97/1/2), Village - Madhawgarh, Tehsil - Ghattiya, Dist. Ujjain (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

आज दिनांक 15/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक कुमावत (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 14/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र में लगभग 07 पेड़ लगे हैं तथा प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र की जो इमेज ऑनलाईन अपलोड की गई तथा जो प्रस्तुतीकरण में दिखाई जा रही है, उसमें अंतर है। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में सही स्थिति की जानकारी प्रमाणित दस्तावेजों सहित तथा आवंटित खनन क्षेत्र में लगे पेड़ों की इवेंट्री (उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित) आगामी 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 11/01/2023 को समिति के समक्ष रखा गया, परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक कुमावत (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पूर्व दिशा में 365 मीटर पर रोड़ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मुरुम का खनन होने के कारण ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2000 दिनांक 17/11/22 के द्वारा सूचित किया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022-23 में तैयार की गई है जबकि उत्खनिपट्टा जिला डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट होने के पश्चात् स्वीकृत किया गया है। उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया (उत्खनि पट्टा संचालन) पूर्ण हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम – 10,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.60 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जनवरी 2023**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम माधवगढ़ के प्राथमिक स्कूल में टंकी सहित शुद्ध पैयजल के लिए वॉटरफिल्टर लगाया जायेगा	30,000
ग्राम माधवगढ़ के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में स्ट्रेचर एवं वीलचेयर प्रदान की जाएगी	45,000
<b>कुल</b>	<b>75000</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	330
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	170
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	700
4	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल आदि स्थानीय प्रजातियाँ	200
<b>कुल वृक्षारोपण</b>			<b>1400</b>

**15. Case No 9541/2022 M/s. Euphoria Mines and Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Singrampur River Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (13000 Cum per annum) (Khasra No. 53, 369), Village- Singrampur, Tehsil-Bijawar, District-Chhatarpur (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 53, 369), Village- Singrampur, Tehsil-Bijawar, District-Chhatarpur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1867 दिनांक 02/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बन्ने नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-44 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-36000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 13,000 m<sup>3</sup>/year घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 13,000 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये । ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में एक छोटी जल रोकने की संरचना बनी हुई है तथा पूर्व दिशा में भी एक छोटा सा सिविल स्ट्रकचर बना हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जल रोकने की संरचना के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में 250 मीटर को सेटवेक दोनो ओर छोड़ा गया है तथा सिविल स्ट्रकचर के दोनो ओर 50 मीटर का सेटवेक छोड़ा गया है जिस कारण लगभग 0.93 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 13,000 घन मीटर है (लगभग 54 घन मीटर प्रति दिवस) जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 13000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.40 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.83 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 06.90 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियाँ चयनित कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे ।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कटंग बॉस, जामुन कहवा खस, नागर मोथा , खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	2200
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आवागमन क्षेत्र में	कटंग बॉस, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	100
2	ग्राम सिंगरामपुरा के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, पुत्रंजीवा, मौलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	100
कुल			2400

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम सिंगरामपुरा, के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में रंगाई, पुताई, फर्नीचर(चार नग लकड़ी की कुर्सीयाँ, दस बेंच एवं डेस्क)	60,0000 / -

**618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जनवरी 2023**

**16. Case No 9542/2022 M/s. Euphoria Mines and Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Singrampura River Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (15000 Cum per annum) (Khasra No. 189, 658), Village-Narayanpura, Tehsil-Bijawar, District-Chhatarpur (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 189, 658), Village- Narayanpura, Tehsil-Bijawar, District-Chhatarpur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ. प्र.उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1860 दिनांक 02/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बन्ने नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-43 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-36000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000 m<sup>3</sup>/year घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी दिशा में एक रपटा बना हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह रपटा नदी के अप-स्ट्रीम पर होने के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में 250 मीटर को सेटवेक छोड़ा गया है जिस कारण लगभग 0.54 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 15,000 घन मीटर है (लगभग 62.50 घन मीटर प्रति दिवस) जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन दक्षिण दिशा से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 15000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.40 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.83 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 06.90 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियों चयनित कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 05 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कटग बॉस, जामुन कहवा खस, नागर मोथा, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2200
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आवागमन क्षेत्र में	कटग बॉस, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	100
2	ग्राम नारायणपुरा के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, पुत्रंजीवा, मौलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
कुल			2400

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम नरायणपुरा, के शासकीय विद्यालय में दो कम्प्युटर, प्रिंटर, प्रिंटर, टेबल के साथ नदी के किनारे पर स्थित कुएं की जगत एवं एक छोटे स्नानागार का निर्माण	70,0000 / -

**17. Case No 9548/2022 Smt. Indra Farkya, Owner R/o, Shamgarh, Tehsil-Shamgarh, District-Mandsaur (MP)-456010 Prior Environment Clearance for Takrawad Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11400 Cum per annum) (Khasra No. 870), Village-Takrawad, Tehsil- Shamgarh, District-Mandsaur (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 870), Village-Takrawad, Tehsil-Shamgarh,, District-Mandsaur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती इंद्रा फरक्या और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2787 दिनांक 10/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 80 मीटर तथा उत्तर दिशा में 235 मीटर पर कच्चा रास्ता तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 520 मीटर पर आबादी है ।

- (अ) प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में गूगल इमेज अनुसार एक कार्यरत खदान दृष्टिगत हो रही है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2787 दिनांक 10/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान दर्शायी गई है जिसमें यह उल्लेखित है कि 01 अस्थायी अनुज्ञा रकबा 4.90 हे. अवधि दिनांक 14/07/20 से 05/9/22 तक है किंतु प्रभारी अधिकारी ने पत्र में यह स्पष्ट नहीं लिखा कि इस अस्थाई अनुज्ञा पर कार्य अभी जारी अथवा समाप्त हो गया है क्योंकि

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

प्रमाण-पत्र समाप्ती अवधि (05/9/22) के पश्चात् दिनांक 14/12/22 को जारी किया गया है अतः इस संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी से स्थिति स्पष्ट कराई जाये।

- (ब) आज दिनांक 11/01/23 को श्री मुहम्मद अमीन, पता 92 गोपालपुरा, बडवाह जिला खरगोन ने एक शिकायत सदस्य सचिव, सिया एवं सेक को प्रस्तुत की है जिसमें यह लिखा है कि प्रकरण क्रमांक 9548/2022 में आवेदन में परिवर्तन कर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि जहां पर यह खदान स्वीकृत की गई है वहां पर तालाब आ रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए आवेदक ने उक्त क्षेत्र को अन्य जगह पर स्थानान्तरित कर दिया है जिससे गूगल पर के.एम.एल. प्रतिबंधित दूरीयो से बाध्य नहीं ओर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर सके। शिकायत में यह भी उल्लेखित है कि यह खदान खसरा न. 870 में स्वीकृत है परन्तु इसे खसरा न. 877, 865, 867 में स्थानान्तरित किया गया है अतः इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति को खारिज किया जाये।

समिति ने उपरोक्त शिकायत का अवलोकन कर निर्णय लिया कि चूंकि इस प्रकरण में उपरोक्त बिंदु (अ) अनुसार संबंधित खनिज अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखे जाने का निर्णय लिया गया है अतः शिकायत के संदर्भ में भी संबंधित खनिज अधिकारी से स्थिति स्पष्ट कराई जाये एवं तदुपरांत प्रकरण में निर्णय लिया जाये।

(चंद्र मोहन ठाकुर)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 11 जनवरी 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

### **Annexure- 'B'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 11 जनवरी 2023

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
  - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 11 जनवरी 2023

- ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

#### **Annexure- ‘C’**

#### **Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minable Potential of sand mine.
  - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.

33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

35. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
36. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
37. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
38. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

### खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।

## 618वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी 2023

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

**नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।